2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की होगी इंटरनेट अर्थव्यवस्था

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 10 फरवरी

भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था पिछले साल की तुलना में 2021 में 50 प्रतिशत बढ़ी है। साथ ही यह 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकती है। परामर्श फर्म रेडसियर की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है।

इंटरनेट की पहुंच में तेज बढ़ोतरी, इंटरनेट की हाई-स्पीड पहुंच, ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल सामग्री की खपत में तेजी की वजह से मजबूती से विस्तार को बल मिलेगा। भारत की आबादी बहुत ज्यादा बहुलतावादी है, ऐसे में एक सेग्मेंट की जरूरतें दूसरे सेग्मेंट से अलग हो सकती हैं। इसे देखते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के डिजिटल उपभोक्ता का आधार को व्यापक रूप से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है।

पहला सेग्मेंट 8 से 10 करोड़ लोगों का है, जिसकी सालाना आमदनी 12,000 डॉलर से ज्यादा है और यह मुख्य रूप से महानगरों में रहती है और बेहतर गुणवत्ता की सेवाओं की उम्मीद करती है। कुछ कारोबारियों ने सफलतापूर्वक वैश्विक मॉडल अपनाया है, जिससे इस समुदाय को सेवाएं प्रदान की जा सकें।

2021 में 50 प्रतिशत बढ़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था

- पहुंच बढ़ने, तेज रफ्तार, ऑनलाइन खरीद बढ़ने व डिजिटल सामग्री की खपत बढ़ने का असर
- रेडसियर की रिपोर्ट में इंटरनेट उपभोक्ताओं को 3 हिस्सों में बांटा गया है
- बिजनेस टु बिजनेस में भी डिजिटल क्रांति का मिलेगा इस क्षेत्र को लाभ

दूसरा तबका वह है, जिसकी सालाना आमदनी 5,000 से 12,000 डॉलर सालाना आमदनी है। यह तबका बजट को लेकर बहुत सचेत होता है। इस डिजिटल आबादी की अनुमानित संख्या 10 से 20 करोड़ है।

अंतिम तबका वह है, जिसकी आबादी 40 से 50 करोड़ है और यह आबादी ग्रामीण क्षेत्र में और मझोले शहरों में रहती है। इसकी सालाना आमदनी 5000 डॉलर से कम है और संभवत: इस तक पहुंचना कठिन है और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल हस्तक्षेप ज्यादा है। यह संभवत: डिजिटल क्षेत्र में पहुंच के हिसाब से सबसे महत्त्वपूर्ण आबादी है। वक्त की जरूरत है कि इनकी समस्याओं का गहराई से समाधान किया जाए।

रेडसियर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्नाकुलर फर्स्ट ऐप तीसरी श्रेणी में आने वाले लोगों को समाधान दे रहे हैं और ये बड़े टीएएम (टोटल एड्रेसेबल मार्केट) तक पहुंचने में सक्षम हैं। साथ ही एक चैनल का तरीका अपना कर और सुपर ऐप के माध्यम से इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।

भारत की नई डिजिटल क्रांति बी2बी (बिनेजस टु बिजनेस) के क्षेत्र में तकनीक की स्वीकार्यता के साथ और बढ़ेगी। वित्त वर्ष 21 में एसएएएस मार्केट का बाजार करीब 3.5 अरब डॉलर का रहा है, यह 18 प्रतिशत सीएजीआर के साथ वित्त वर्ष 26 तक बढ़कर 8 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। प्रमुख इंटरनेट अर्थव्यवस्था में ई-टेल, ईहेल्थ, फूडटेक, ऑनलाइन मोबिलिटी और बिलपे और रिचार्ज की वजह से तेजी आई है। खासकर कोविड के बाद इसका इस्तेमाल बढ़ा है और कोविड के बाद रिकवरी में यह और मजबूत बनकर उभर रहा है।

रेडसियर के संस्थापक और सीईओ अनिल कुमार ने कहा, 'भारत की 1 लाख करोड़ डॉलर की उपभोक्ता इंटरनेट अर्थव्यवस्था में विभिन्न अहम इंटरनेट क्षेत्रों जैसे ई-टेलिंग, ई-हेल्थ, फूडटेक, ऑनलाइन मोबिलिटी और क्विक कॉमर्स की अहम भूमिका होगी और खपत वाली अर्थवव्यवस्था में यह सब मिलकर मजबूत आधार तैयार करेंगे।'

ईडी को फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों संजय चंद्रा, अजय चंद्रा और अन्य के खिलाफ दाखिल किए जाने वाले आरोप पत्र में अदालत द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट का इस्तेमाल करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ ने ईडी को ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट पर भरोसा करने की तब अनुमति दी जब जांच एजेंसी ने कहा कि यह चंद्रा बंधुओं के खिलाफ मामले को और मजबूत करेगी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कहा कि एजेंसी अगले सप्ताह धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी। पीठ ने कहा, 'इस अदालत ने 6 अक्टूबर 2021 को चंद्रा बंधुओं के साथ फॉरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया था और चूंकि अब प्रवर्तन निदेशालय इस रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता है, इसलिए एजेंसी अदालत से अनुमति और आदेश में संशोधन का अनुरोध कर रही है।' पीठ ने कहा कि वह अनुमति दे रही है। साथ ही स्पष्ट किया कि पहले का आदेश ईडी को फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर भरोसा करने से नहीं रोकेगा। पीठ ने यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को जमानत के लिए निचली अदालत जाने की अनुमति दे दी है। *भाषा*

उद्यमियों को व्यापार कानून की 26,134 धाराओं का डर : रिपोर्ट

दीपशेखर चौधरी
बेंगलूरु, 10 फरवरी

भारत सरकार कारोबार सुगमता सुधारने के लिए कदम उठा रही है और बेहतर वैश्विक रैंकिंग के दावे कर रही है, वहीं एक नए अध्ययन में यह सामने आया है कि भारत के व्यापार कानूनों में कारावास की सजा देने वाली 26,134 धाराएं हैं, जिनका सामना उद्यमियों और कॉर्पोरेट्स को करना पड़ता है।

देश के 5 राज्यों में व्यापार कानून में कारावास की सजा देने वाले 1,000 से ज्यादा कानून हैं। टीमलीज रेगटेक और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक अध्ययन के मुताबिक इस तरह के गुजरात में 1,469, पंजाब में 1,273, महाराष्ट्र में 1,210, कर्नाटक में 1,175 और तमिलनाडु में 1,042 कानून हैं।

भारत में कारोबार को प्रशासित करने वाले 1,536 कानूनों में से आधे से ज्यादा में जेल की सजा का प्रावधान है। कारोबार करने के लिए 69,233 अनुपालन करने होते हैं, जिसमें से 37.8 प्रतिशत (हर 5 में से करीब 2) में जेल की सजा का प्रावधान है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'इस नियामकीय कोलेस्ट्रॉल की वजह से भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.6 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है और भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,900 डॉलर है, जो बांग्लादेश, सीरिया व नाइजीरिया से भी कम है।'

- **ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और टीमलीज रेगटेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कारोबार को प्रशासित करने वाले 1,536 कानूनों में से आधे से ज्यादा में जेल की सजा का प्रावधान**
- **5 राज्यों में व्यापार कानून में कारावास की सजा देने वाले 1,000 से ज्यादा कानून**
- **भारत का जीडीपी 2.6 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है, वहीं इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,900 डॉलर है, जो बांग्लादेश, सीरिया व नाइजीरिया से भी कम**

इसमें कहा गया है, 'बहुत ज्यादा कानून होने की वजह से फर्मों को एक पूर्णकालिक अनुपालन विभाग बनाना पड़ता है। इससे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। 150 से ज्यादा कर्मचारियों वाले एमएसएमई को 500 से 900 अनुपालन करने होते हैं, जिसकी लागत 12 से 18 लाख रुपये सालाना आती है।'

जेल की सजा वाली आधी से ज्यादा धाराओं में कम से कम एक साल के दंड का प्रावधान है। इनमें से कुछ धाराओं में प्रक्रिया के उल्लंघन को आपराधिक बना देती हैं, जबकि कुछ में मामूली चूक की वजह से सजा का प्रावधान है और यह सजा जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या धोखाधड़ी करने की तुलना में ज्यादा हैं। कुछ कानूनों में अनुपालन रिपोर्ट की देरी से या गलत फाइलिंग को अपराध माना गया है और इसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत सजा का प्रावधान है। जेल की सजा की ज्यादातर धाराएं श्रम कानूनों से जुड़ी हैं, जिसमें कानून के मुताबिक 50 से ज्यादा धाराएं हैं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत का उद्यमशीलता परिदृश्य कानूनों, नियमों और विनियमों से भरा पड़ा है, जिन्होंने कारोबार में बाधाएं खड़ी की हैं। उदाहरण के लिए फैक्टरीज अधिनियम, 1948 में 58 नियम हैं, जिनमें जेल संबंधी 8,682 धाराएं हैं।

JINDAL CAPITAL LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L65910DL1994PLC059720
Registered Office: 201, Aggarwal Plaza Sector - 9, Rohini, North West Delhi – 110 085, India.
Phon: 011-23841536 | **Fax:** 011-23840864 | **Email Id:** info@jindalcapital.in | **Website:** www. jindalcapital.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors (constituted by the Board of Directors of Jindal Capital Limited, hereinafter referred to as "IDC") on the Open Offer ("Offer") made by Mr. Sadhu Ram Aggarwal ("Acquirer 1"), Mr. Udit Aggarwal ("Acquirer 2"), Ms. Divya Aggarwal ("Acquirer 3"), Ms. Ridhima Aggarwal ("Acquirer 4"), Mr. Rahul Aggarwal ("Acquirer 5"), Ms. Manjula Aggarwal ("Acquirer 6") and CMV Informatics Private Limited ("Acquirer 7") (hereinafter collectively called "Acquirers") to the Public Shareholders of Jindal Capital Limited ("Target Company" or "TC") under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("Takeover Regulations").

1	Date	February 10, 2022
2	Name of the Target Company (TC)	Jindal Capital Limited
3	Details of the Offer pertaining to the TC	Offer is being made by the Acquirers for the acquisition of upto **18,74,106** fully paid-up equity shares of face value ₹ 10/- each, (**"Offer Shares"**) representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the TC at a price of ₹ **9.72** (Rupees Nine and Seventy Two Paisa only. The price includes interest of ₹ 0.72) per Equity Share (the **"Offer Price"**), payable in cash in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. Public Announcement dated November 27, 2020 (**"the PA"**), the Detailed Public Statement dated December 07, 2020 (**"the DPS"**), Draft Letter of Offer dated December 11, 2020 (**"the DLoF"**) and the Letter of Offer dated February 07, 2022 (**"the LoF"**) (PA, DPS, DLoF and LoF collectively referred to as Offer Documents) issued by Khambatta Securities Limited, the Manager to the Open Offer (**"the Manager"**) on behalf of the Acquirers.
4	Name of the Acquirers	**Acquirers:** 1. Mr. Sadhu Ram Aggarwal ("Acquirer 1") 2. Mr. Udit Aggarwal ("Acquirer 2") 3. Ms. Divya Aggarwal ("Acquirer 3") 4. Ms. Ridhima Aggarwal ("Acquirer 4") 5. Mr. Rahul Aggarwal ("Acquirer 5") 6. Ms. Manjula Aggarwal ("Acquirer 6") 7. CMV Informatics Private Limited ("Acquirer 7")
5	Name of the Manager to the Offer	Khambatta Securities Limited C-42, South Extension Part - II, New Delhi - 110049, India | Tel.: 011 4164 5051 eMail: vinay@khambattasecurities.com Website: www.khambattasecurities.com Contact Person: Mr. Vinay Pareek and Mr. Chandan Mishra SEBI Registration No.: INM 000011914
6	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	1. Mr. Ashutosh Aggarwal (Chairperson) 2. Mr. Rohit Gupta (Member)
7	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity Shares owned, any other contact / relationship), if any	IDC members are Non-Executive and Independent Directors on the Board of the TC. None of the IDC members hold any shares or other securities in the TC. None of the IDC members have entered into any other contract / relationship with the TC except as directors on the board of the TC and as chairperson/ member of the Board Committees.
8	Trading in the Equity Shares / other Securities of the TC by IDC Members	None of the IDC membershas traded in Equity Shares / other securities ofthe TC during the period of 12 months prior to the date of Public Announcement November 27, 2020 and till the date of this recommendation.
9	IDC Member's relationship with the the Acquirers (Director, Equity Sharesowned, any other contact/ relationship), if any	None of the IDC Members: i) is a director of the Acquirer; ii) holds any equity / other securities in the Acquirer; iii) has any other contracts/relationship with the Acquirer.
10	Trading in the Equity Shares / other securities Shares of Acquirer by IDC Members	None of the members of the IDC have any contracts / relationships/ directorships / shareholding with any Acquirer.
11	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC believes that the Offer is in compliance with the requirements of the Takeover Regulations and is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision.
12	Summary of reasons forrecommendation	IDC has perused the PA, DPS, DLoF, LoF issued in relation to the Open Offer by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers and particularly noted the following, while making the recommendation: • The equity shares of the Target Company are not frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the Takeover Regulations. • As per the valuation report dated 27 November, 2020 issued by CA Ankush Garg, Registered Valuer – Securities or Financial Assets with IBBI and having office at A - 3 / 85, Sector - 3, Rohini, Delhi – 110085 – The fair value of Equity Shares is ₹ 8.46 • The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for any acquisition under an agreement attracting the obligation to make of PA of an Open Offer i.e. the price per share under the Share Purchase Agreement is ₹ 9.00. • Further, the interest of INR 0.72 per share is calculated pursuant to Regulation 18 (11A) of SEBI Takeover Regulations @ 10% p.a. for the delay in payment to shareholders due to delayed statutory approval. Based on the above, the IDC is of an opinion that the Offer Price of ₹ 9.72 per Equity Shares is in compliance with the SEBI (SAST) Regulations and hence is fair and reasonable. The Public shareholders of the Target Company are, however, advised to independently evaluate the open offer and take informed decision whether or not to tender their shares in the Open offer.
13	Details of Independent Advisors, if any	None
14	Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of
Jindal Capital Limited
Sd/-
Mr. Ashutosh Aggarwal
Chairperson of the IDC
DIN: 09341810

Place: New Delhi
Date: February 10, 2022

Raka

60-65 हजार करोड़ रु जुटाएगी एलआईसी

पृष्ठ 1 का शेष...

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने शेयर बिक्री का जिम्मा संभालने के लिए 16 निवेश बैंकों को नियुक्त किया है। बाजार में आईपीओ लाने से पहले निर्गम को बाजार नियामक सेबी से मंजूरी लेनी होती है। सेबी आईपीओ प्रस्ताव को मंजूरी देने में एक माह से अधिक समय लगा देता है। मगर एलआईसी के निर्गम को तीन हफ्ते में मंजूरी मिलने की संभावना है।

एलआईसी जीवन बीमा बाजार में सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। मगर निजी कंपनियों के विविधता भरे उत्पादों और मजबूत वितरण नेटवर्क के कारण एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी कम हो रही है। जनवरी 2022 में नए कारोबार के प्रीमियम में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी 61.61 फीसदी रही, जो अप्रैल 2021 में 66.18 फीसदी थी।

वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में एलआईसी को 1,437 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था जबकि इससे एक साल पहले की समान अवधि में उसका मुनाफा महज 6.14 करोड़ रुपये था। निवेश से आय बढ़ने के कारण एलआईसी का मुनाफा बढ़ा है।

एलआईसी का एयूएम 1 लाख करोड़ रु बढ़ा

सुब्रत पांडा
मुंबई, 10 फरवरी

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) सितंबर 2021 में बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो मार्च 2021 में 37 लाख करोड़ रुपये थी। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी।

कारोबार बढ़ा

इसका एयूएम निजी क्षेत्र के सभी बीमाकर्ताओं के एयूएम से 3 गुना ज्यादा और दूसरे सबसे बड़ी जीवन बीमाकर्ता एसबीआई लाइफ के एयूएम से 15 गुना ज्यादा है। सूत्रों ने कहा कि एसबीआई लाइफ का एयूएम सितंबर 2021 में 2.4 लाख करोड़ रुपये था।

साथ ही सितंबर 2021 तक एलआईसी के एयूएम का 61.67 प्रतिशत पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज में, 37 प्रतिशत नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीधारक निवेशों में, 1.15 प्रतिशत यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज में और 0.16 प्रतिशत शेयरधारकों के निवेश में है।

उम्मीद की जा रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज बीमा कंपनी इस सप्ताह बाजार नियामक प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास अपना मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पेश करेगी। यह संभवत: भारत के पूंजी बाजारों में सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जिसके माध्यम से सरकार 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी।

एलआईसी देश में सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में से एक है, जिसका एकल आधार पर कुल निवेश 39.49 लाख करोड़ रुपये है और सितंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक इसने 9.78 लाख करोड़ रुपये इक्विटी में निवेश किया है।

केंद्र की गति सीमा पर न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा को 120 किमी प्रति घंटे तय करने वाली अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है। गडकरी ने आगे कहा कि वह एक विधेयक को अंतिम रूप देना चाहते हैं जिसे विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए वाहनों की गति सीमा को संशोधित करने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'मद्रास उच्च न्यायालय ने राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा कम कर दी है। हमने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की है।' *भाषा*

फ्रेश टु होम का 150 शहरों में विस्तार

ई-कॉमर्स के माध्यम ताजी मछलियों व मांस का कारोबार करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पूरी तरह से एकीकृत ऑनलाइन ब्रांड फ्रेश टु होम बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है और वह उत्तर प्रदेश, एनसीआर, पंजाब, कोलकाता और राजस्थान के 150 से ज्यादा शहरों में अपने उत्पादों को उपलब्ध करा रही है। अन्य स्थलों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। *बीएस*

निवेशक संरक्षण समिति का पुनर्गठन

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष (आईपीईएफ) पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति निवेशकों को शिक्षित करने और उनके संरक्षण की उन गतिविधियों के बारे में सुझाव देती है, जिसे नियामक खुद या किसी एजेंसी के जरिए कर सकता है। अब इस 8 सदस्यीय समिति के चेयरमैन सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम होंगे। सेबी की वेबसाइट पर डाली गई सूचना से यह जानकारी मिली है। *भाषा*

टोरंट ने किया 25 मेगावॉट के सौर संयंत्र का अधिग्रहण

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 10 फरवरी

टोरंट पावर लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसने ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) द्वारा संचालित 25 मेगावॉट के सौर बिजली संयंत्रों का अधिग्रहण 163 करोड़ रुपये में करने का फैसला किया है।

अहमदाबाद की उत्पादन और वितरण कारोबारी ने इन दो कंपनियों के साथ विजुअल परसेप्ट सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर के अधिग्रहण के लिए शेयर खरीद समझौता किया है। यह एसपीवी गुजरात में 25 मेगावॉट क्षमता के सौर बिजली संयंत्र का परिचालन करता है, जिसका गुजरात ऊर्जा विकास निगम (जीयूवीएनएल) के साथ 25 साल की अवधि के लिए बिजली खरीद समझौता है।

बीएस सूडोकू 4278

परिणाम संख्या 4277

2								5
3						6		
					6		3	1
7						5		
8				9				
6	9		3	2		4		
		8		5	1	7		4
					4			8
		5	2					

5	4	3	1	8	9	6	2	7
7	8	2	4	6	3	1	5	9
6	9	1	2	5	7	3	8	4
4	2	7	5	3	1	9	6	8
8	1	6	9	7	2	4	3	5
9	3	5	6	4	8	7	1	2
1	5	8	3	9	4	2	7	6
3	7	4	8	2	6	5	9	1
2	6	9	7	1	5	8	4	3

कैसे खेलें?
हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल
★★★★☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2120/2125, गेहूं शरबती 2850/3000, चावल शरबती सेला 4100/4150, स्टीम 5150/5250, लालमती 4400/4500, चावल (सोना) 4200/4300, दाल अरहर सवा नं. 7800/7900, पटका 8700/9300, रिजैक्शन 6500/7500, चना दाल 5675/5800, चना देशी छना 5600/5700, चना चापा छना 5650/5800, एग्रो प्योर बेसन 2280, मटर विदेशी 7100/7200, उड़द साबुत (काला)6300/7300, दाल उड़द (काली) 7000/8200, उड़द धोया 7800/8800, मसूर छोटी 7100/7200, मलका 8400/8700, किरानाः जीरा 19500/21500, लालमिर्च गुंटूर 18000/23500, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 5700/5800, धनिया एमपी 10700/12700, छोटी इलायची (किलो) 1100/1575, बड़ी इलायची 730/760, कालीमिर्च (किलो) 515/560, सुपारी (किलो) 530/560, सौंफ मोटी 9400/11800, मंगरैल 22500/23500, चिरोंजी (किलो) 1100/1250, मखाना 475/700

कानपुर
गेहूं लूज 2135/2140, जौ 1975/2000, चावल मसूरी 2400/2500, चावल मोटा 2250/2400, देशी चना 5100/5150, चना छना 5600/5750, दाल चना 5650/5800, विदेशी मटर ×, पिचकी 4400/4500, मटर दाल 7000/7200,अरहर लेमन 6400/6425, दाल अरहर 9000/9300, स्पेशल 8200/8600,उड़द एसक्यू 6700/6710, एफएक्यू 6175/6200, राजमा चित्रा 9700/13000, मूंग 5500/6000, मसूर छोटी 7100/7200, छांटी 8600/8900, सरसों 6900/7100, तिल सफेद 9900/10000, सोया (टीन) 2200/2250, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)2500/2550, सरसों खल 3200/3300, पामोलिन 2200/2260, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1850/1950, मधुसूदन देशी घी 6375, वासुदेव 6100, परम प्रीमियम 6400, पदम श्री 6350, लीलाधर 6150, अलसी 9600/9800, धनियाः लोकल 9900/10100, राजस्थान 10500/10700, बढ़िया 11500/12500, हल्दी 9300/11500, जीरा 19400/21000, अजवायन 14000/18000, मेथी 8200/8500, मखाना 470/700, कालीमिर्च (किलो) 500/560, लालमिर्च (किलो) तेजा 195/245, (334) न. 175/190, सुपारी (किलो) केरल 530/560, कर्नाटक चिकनी 520/540, गोला 23000/24000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1123, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1082, फ्लैक 1053, डीएमओ 940, टरपीन लैस बोल्ड 1108

जयपुर
दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मूंग मोगर 7900/8000, मोटा 8300/8800, उड़द मोगर 7700/7800, मोटा 8300/8800, चौला मोगर ×, मोठ मोगर 7800/8000, मूंग दाल छिलका देशी 8000/8500, मलका 8400/8700, अरहर 7900/8800, मटर दाल 7000/7500, चना दाल मीडियम 5800/5900, बोल्ड 5900/6000, दलहनः उड़द साबुत देशी 6400/6500, मटर सफेद 6500/7000, मोठ साबुत 6300/6500, काबली चना 7000/8500, चना (डिली.) 5000/5050, मूंग 6000/6500, राजमा शर्मिली 9000/9500, राजमां चित्रा 12000/13500, किरानाः हल्दी निजामाबाद 10000/10500, सांगली 10500/11500, हल्दी राजापुरी 14000/17000, लालमिर्च 18000/24000, कालीमिर्च (किलो) 550/650, धनिया 10600/11500, जीरा 19000/23000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)150, राइसब्रान (अखाद्य) 145, खल सरसों 3200, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1060, लाल ×, कंटीन्यूअस 1015, सरसों (टन) 26200, सूरजमुखी (टन) 25300, अनाजः गेहूं 2190/2200, आटा (50 किलो)1150, मैदा 1260, चोकर (45 किग्रा) 1050, चोकर (30 किग्रा) 680, मक्की एमपी 2290/2300

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 10000/13500, अरहर दाल 8700/9400, उड़द साबुत 7500/8400, उड़द धोया 8500/9400, छिलका 8000/9000, दाल मसूर 8500/9400, चनादाल 5700/5800, एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)2270, काबली चना 5900/8700, मूंग साबुत 7000/8500, मूंग धोया 8000/9600, *एनएनएस*